Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding telecommunication problem in Ladakh.

श्री जामयांग त्सेरिंग नामग्याल (लद्दाख): माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान लद्दाख में टेली कॉम्युनिकेशन की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । लद्दाख का बार्डर चीन और पाकिस्तान के साथ लगता है । यहां विलेजेज़ और हैमलेट्स 350 हैं, जहां मोबाइल और टेली कॉम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है । अब विंटर सीज़न आ रहा है, इस मौसम में यहां 12-15 फीट तक बर्फ होती है । इसमें लोगों के माल-मवेशी दब जाते हैं, पूरा चारागाह खत्म हो जाता है और वहां एक पेशेंट को इवैक्युएट करने के लिए कम्युनिकेशन तक उपलब्ध नहीं हो पाता है । पिछले साल तक जो 344 डीएसपीटीज चलते थे, वे सारे बंद हो गए हैं । इस बार के विंटर में हम कैसे जीवित रहेंगे इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं । मैं आपका बताना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र दरास में आज का तापमान -24.8 है । ऐसी दुर्गम स्थिति में लोगों के लिए कम्युनिकेशन का साधन होना बहुत जरूरी है । वहां कमर्शियल वायबिलिटी नहीं होने के कारण प्राइवेट सेक्टर तथा बीएसएनएल का सेटअप नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां ऑपरेशनल कॉस्ट हाई है और रिटर्न लेस है । इसलिए मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि युनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंडिंग के तहत पूरे लद्दाख को टेलीकम्युनिकेशन के साथ जोड़ दिया जाए । मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि मैंने पिछले पांच महीनों में जितने पत्र भेजे, मुझे सबके जवाब मिले, लेकिन एक्शन बिल्कुल नहीं हुआ । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूं कि पिछले पांच सालों में यूएसओएफ ने लद्दाख को कितना पैसा दिया है- वर्ष 2014 से 2015 और वर्ष 2015-2016 में शून्य, वर्ष 2016 से 2017 में 914000, वर्ष 2017 से 2018 में 134000 तथा वर्ष 2018 से 2019 में 154000 । अगर डिपार्टमेंट मुझे बोल देता तो मैं किसी सरपंच से इससे ज्यादा पैसा दिलवा देता । मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं । सरकार पूरा ध्यान रख रही है, पूरे देश को डिजिटल इंडिया के

साथ जोड़ रही है । लेकिन, डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो इस काम को ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं ।

यह शेम की बात नहीं है । अगर मैं यूपीए की स्थिति को बता दूं तो ये लोग पूरे देश के सामने आ जाएंगे कि इन्होंने क्या किया है । अभी आलोचना करने का समय नहीं है ।

डिजिटल कम्युनिकेशन नहीं होने के कारण जितनी भी सरकार की स्कीम्स हैं, चाहे वह मनरेगा, ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, उज्ज्वला योजना, ऑनलाइन टेंडर आदि हैं, वहां ये सारी स्कीम्स ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाती हैं । इसलिए, मेरा सरकार से निवेदन है कि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद इसको प्रॉयोरिटी देकर पूरे लद्दाख क्षेत्र को डिजिटल लद्दाख बनाने की कृपा करें । यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय अध्यक्ष: फिर हर शून्य काल का माननीय मंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा ।